

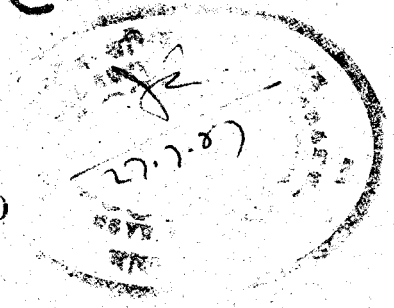


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section. 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 262]
No. 262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 15, 1987/वैशाख 25, 1909
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 15, 1987/VAISAKHA 25, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(वैकिण प्रभाग)
नई दिल्ली, 15 मई, 1987
अधिसूचना ।

सा. का. नि. 506(अ).—केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (सचिव की शक्तियां और कर्तव्य) नियम, 1987 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) अभिप्रेत है।

(ख) “न्यायपीठ” से धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की न्यायपीठ अभिप्रेत है।

(ग) “बोर्ड” से अधिनियम की धारा 4 के अधीन स्थापित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, वहां बोर्ड की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने वाली न्यायपीठ है।

(घ) “अध्यक्ष” से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(ङ) “प्रचालन संबंधी अभिकरण” से बोर्ड द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अपने अभिकरण के रूप में कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(च) “निर्देश” से अधिनियम की धारा 15 के अधीन बोर्ड को किया गया कोई निर्देश अभिप्रेत है।

(छ) “सचिव” से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है।

3. साधारण (1) सचिव, बोर्ड का प्रधान अधिकारी होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(2) बोर्ड, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, सचिव से ऐसी सहायता ले सकेगा जैसी वह उचित समझे और सचिव बोर्ड को सहायता करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) विशिष्टतया और इस नियम के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सचिव को निम्नलिखित शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन किए गए बोर्ड के आदेश के अनुसरण में, किसी प्रचालन संबंधी अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की संवीक्षा करेगा और बोर्ड को उस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि क्या उक्त रिपोर्ट उन विषयों की बाबत पूर्ण है जिनमें बोर्ड द्वारा प्रचालन संबंधी अभिकरण से पूछताछ करना अपेक्षित था या नहीं, और प्रचालन संबंधी अभिकरण द्वारा पूछताछ करने के लिए यदि कोई हो, और उसके द्वारा और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड का निर्देश प्राप्त करेगा।

(ख) सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन बोर्ड के किसी आदेश के अनुसरण में किसी प्रचालन संबंधी अभिकरण द्वारा तैयार की गई स्कीम या अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के अधीन बोर्ड के किसी आदेश के अनुसरण में किसी प्रचालन संबंधी अभिकरण द्वारा तैयार की गई किसी नई स्कीम की संवीक्षा करे, और विषयों पर कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि क्या उक्त स्कीम बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है या नहीं।

(ग) सचिव को, केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, किसी अनुसूचित बैंक या किसी अन्य बैंक, लोक विस्तीय संस्थाओं या राज्य स्तर की संस्थाओं या अन्य कार्यालयों, संस्थाओं, कंपनियों, फर्मों से ऐसी जानकारी जो अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दुष्प्रभावपूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझी जाए, संग्रहण करने और उक्त जानकारी को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(घ) सचिव, किसी औद्योगिक कंपनी के, धारा 23 की उपधारा (1) के उपबंधों को कंपनी द्वारा अनुपालन के संबंध में जानकारी ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा और अध्यक्ष से उस विषय में आगामी कार्रवाई यदि कोई हो, किए जाने के बारे में निर्देश प्राप्त कर सकेगा।

(ङ) बोर्ड की पदीय मुद्रा, सचिव के लिखित में प्राधिकार के सिवाय, किसी आदेश, समन, अन्य आदेशिका या बोर्ड द्वारा जारी की गई किसी प्रमाणित प्रति या किसी अन्य दस्तावेज पर नहीं लगाई जाएगी।

(च) सचिव, बोर्ड के अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(छ) बोर्ड की पदीय मुद्रा, सचिव की अभिरक्षा और नियंत्रण में होगी।

4. सचिव की अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य :

(1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट अपनी शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त सचिव को निम्नलिखित अतिरिक्त शक्तियां होंगी और वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(I) सभी निर्देशों, आवेदनों, रिपोर्टों, पत्रों, अभ्यावेदनों और अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करेगा,

(II) बोर्ड को किए गए किसी निर्देश से उत्पन्न सभी प्रश्नों का, बोर्ड के कार्यालय में उनके रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पूर्व विनिश्चय करेगा,

(III) अधिनियमों के अनुसार या अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी निर्देश के संशोधन किए जाने की अपेक्षा करेगा,

(IV) यथास्थिति, अध्यक्ष या संबंधित न्यायपीठों के निर्देशों के अधीन रहने हुए, निर्देशों, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करेगा,

(V) अभिलेखों के प्ररूपिक संशोधन के लिए निर्देश करेगा,

(VI) बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए इजाजत देगा,

(VII) सूचना की तामील, समन, अन्य आदेशिकाओं, नई सूचनाओं जारी करने के लिए आवेदनों, समनों या अन्य आदेशिकाओं या तामील करने के किसी विशिष्ट तंग का आदेश करने की अवधि बढ़ाने के लिए जिसके अंतर्गत सूचना, समनों या अन्य आदेशिकाओं का समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित सेवा भी है, से संबंधित सभी विषयों का निपटारा करेगा।

(2) खंड (II), (III), (IV), (V) और (VI) के अधीन जारी किए गए विनिश्चय या निर्देश के विरुद्ध व्यथित पक्षकर उस तारीख से 15 दिन के भीतर, जिस, को ऐसा विनिश्चय या निर्देश उसे संसूचित किया गया है, अपील अध्यक्ष को की जाएगी और अध्यक्ष का विनिश्चय उस पर अंकित होगा।

5. इन नियमों के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियाँ, सचिव की अन्य शक्तियों के अतिरिक्त होना—(1) इन नियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ और पालन किए जाने वाले कर्तव्यों, उन शक्तियों और कर्तव्यों के अतिरिक्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, अधिनियम की धारा 38 के अधीन विहित की गई हैं, या जो पहले ही किए जा चुके हैं या समय-समय पर बनाए जाएँ।

(2) इन नियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियाँ और पालन के लिए जाने वाले कर्तव्य उन नियमों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हैं, जो अधिनियम की धारा 27 के अधीन अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ या सचिव को बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएँ।

[सं. 2(3)/बीआईएफआर/86]

मन्त्रिपरिषद्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 15th May 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 506(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Board for Industrial and Financial Reconstruction (Secretary's Powers and Duties) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

- (a) "Act" means the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986);
- (b) "Bench" means a Bench of the Board constituted under sub-section (2) of section 12;
- (c) "Board" means the Board for Industrial and Financial Reconstruction, established under section 4 of the Act, and includes, where the context so requires, a Bench exercising the jurisdiction, powers and authority of the Board;
- (d) "Chairman" means the Chairman of the Board;
- (e) "operating agency" means any public financial institution specified by the Board, by general or special order, as it agency;

(f) "reference" means reference made to the Board under section 15 of the Act;

(g) "Secretary" means the Secretary to the Board appointed under sub-section (1) of section 8 of the Act.

3. General.—(1) The Secretary shall be the principal officer of the Board who shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Chairman.

(2) The Board in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary, as it may deem fit, and the Secretary shall be bound to assist the Board.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the provisions of this rule, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, namely :—

- (a) It shall be the duty of the Secretary to scrutinise the report submitted by any operating agency, in pursuance of the order of the Board made under sub-section (2) of section 16 of the Act and submit a report to the Board on the point as to whether the said report is complete with respect to matters which the operating agency was required by the Board to enquire into or not, and seek directions of the Board as to carrying out of further inquiry if any, by the operating agency and submission by it of a further report.
- (b) It shall be the duty of the Secretary to scrutinise the scheme prepared by any operating agency in pursuance of an order of the Board under sub-section (3) of section 17 or a fresh scheme prepared by an operating agency in pursuance of the order of the Board under sub-section (5) of section 18 of the Act, and submit a report on the point as to whether the said scheme has been prepared in accordance with the guidelines specified in the order of the Board.
- (c) The Secretary shall have the right to collect from the Central Government, the Reserve Bank, any scheduled bank or any other bank, the public financial institutions or the State level institutions, or other offices, institutions, companies, firms, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Board under the Act and place the said information before the Board.
- (d) The Secretary may call upon any industrial Company to furnish within such time, as may be specified by him, information in relation to compliance by the company of the provisions of sub-section (1) of section 23 and seek the directions of the Chairman as to further action, if any, to be taken in the matter.

(e) The official seal of the Board shall not be affixed to any order, summons, other process or any certified copy issued by the Board or any other document save under the authority in writing of the Secretary.

(f) The Secretary shall have the custody of the records of the Board.

(g) The official seal of the Board shall be in the custody and control of the Secretary.

4. Additional powers and duties of the Secretary.—(1) In addition to his powers and duties specified in rule 3, the Secretary shall have the following additional powers and perform the following duties, namely :—

- (i) receive all references, applications, reports, letters, representations and other document;
- (ii) decide all questions arising out of any reference to the Board before the same is registered in the office of the Board;
- (iii) require any reference to be amended in accordance with the Act or the regulations made under section 13 of the Act;
- (iv) subject to the directions of the Chairman, or the respective Benches, as the case may be, fix dates for hearing of references; applications or other proceedings;
- (v) direct formal amendment of records;
- (vi) grant leave to inspect the records of the Board;

(vii) dispose of all matters relating to the service of the notice, summons, other process, applications for issue of fresh notices, summons or other process, or for extending time for ordering a particular mode of service including the substituted service by publication of the notice, summons or other process by way of advertisement in the newspapers.

(2) An appeal against the decision of or direction issued by the Secretary under clauses (ii), (iii), (v), (vi) and (vii) shall be made to the Chairman by the aggrieved party within 15 days from the date on which such decision or direction is communicated to him and the decision thereon of the Chairman shall be final.

5. Powers exercisable under these rules to be in addition to other powers of the Secretary.—(1) The powers exercisable and duties to be performed by the Secretary under these rules shall be in addition to those prescribed under any other rules as have already been made or as may be made from time to time, by the Central Government under section 36 of the Act.

(2) The powers exercisable and duties to be performed by the Secretary under these rules are without prejudice to those as may be specified by the Chairman or delegated to the Secretary, by the Board under section 27 of the Act.

[F. No. 2(3)|BIFR|86]

MANTRESHWAR JHA, Jt. Secy.